

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर  
पीठासीन अधिकारी-श्री बलदेवसिंह हाडा

संख्या 03/12

तारीख रजू- 24/02/2012

पुत्र श्री रामनिवास जाति शर्मा निवासी खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।  
बनाम

—प्रार्थी

—अनूपकाश पुत्र शंकरलाल जाति नाई निवासी खण्डार तहसील खण्डार।  
—ग्राम पंचायत खण्डार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खण्डार।

—अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक-01/02/2016

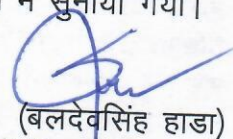
प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत खण्डार द्वारा पत्रावली संख्या 388 निर्णय दिनांक 15/09/90 की पालना में जारी पट्टा 07/10/90 जो अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में 65 वाई 42.5 फुट कुल 307 वर्गगज का जारी किया है के विरुद्ध प्रस्तुत की है व जारी किये गये उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई व मातहत की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश अमल में लाये गये। मातहत की पत्रावली बाबत सरपंच ग्राम पंचायत खण्डार के पत्र क्रमांक 31 दिनांक 07/12/12 व 378 दिनांक 31/08/12 से यह सूचना प्राप्त होने पर कि पंचायत रिकार्ड में उक्त पट्टा मिल नहीं रही है पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के भाई की पत्नी देवी को पंचायत ने 8X8 गज का पट्टा जारी किया था उस पट्टे में रास्ता पश्चिम दिशा की ओर बनाया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को 07/10/90 को जारी पट्टा इस रास्ते की जगह पर जारी किया है जो अवैधानिक है। अतः पट्टा निरस्त किया जावे क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 फर्जी पट्टे के मातहत प्लॉट पर कब्जा करने के प्रयास में है।

अप्रार्थीगण की ओर से स्वयं अथवा कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली को गौर किया। उक्त वाद चल चुका है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश(क.ख.) खण्डार में अप्रार्थी संख्या 1 ओमप्रकाश का पट्टा संख्या 16/2002 इसी पट्टे के बाबत उसके पक्ष में खिग्री हो चुका है। प्रार्थी उक्त वाद में उपस्थित नहीं था लेकिन उस वाद में भी निगरानी में उठायी गई आपत्ति के बारे में विवेचन है इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा उसी आधार पर निगरानी दायर की है। निगरानी के लिये कोई विचारणीय बिन्दु भी नहीं है। यदि उक्त पट्टा विधिवत जारी नहीं हुआ है तथा प्रार्थी का हित प्रभावित है तो उसे अपील चाहिये थी। पट्टा फर्जी है तो संबंधित के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करानी चाहिये थी। सिविल न्यायालय के निष्कर्ष आ चुके हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01/02/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बलदेवसिंह हाडा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर